

कुरुक्षेत्र का सारांश (सितंबर 2026)

1. वैश्विक नेतृत्व की ओर भारत का मार्ग

परिचय

स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, विकसित भारत@2047 को आर्थिक प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक साझेदारी और कानूनी आधार की आवश्यकता है।

आर्थिक प्रतिस्पर्धा और समावेशी विकास

- ❖ कुशल उत्पादन, निरंतर नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आर्थिक प्रतिस्पर्धा को दीर्घकालिक समृद्धि का इंजन बनाते हैं।
- ❖ उत्पादकता में वृद्धि, सरलीकृत नियम, हरित प्रौद्योगिकियाँ और चक्र्रीय मॉडल समृद्धि, पर्यावरणीय लचीलापन और व्यावसायिक दक्षता को मजबूत करते हैं।

- ❖ मानव पूंजी में निवेश युवाओं को सशक्त बनाता है, साथ ही सामाजिक, क्षेत्रीय, लैंगिक और ग्रामीण-शहरी असमानताओं को कम करता है।
- ❖ स्मार्ट शहरों, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल नेटवर्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और ब्लॉकचेन का उपयोग किया जाता है।
- ❖ प्रतिस्पर्धी उद्योग रोजगार सृजित करते हैं, आय में वृद्धि करते हैं और गरीबी में कमी लाते हैं जिससे भारत का वैश्विक आर्थिक नेतृत्व मजबूत होता है।
- ❖ नियामक जटिलता, बुनियादी ढाँचे की कमियाँ, निम्न उत्पादकता और अपर्याप्त अनुसंधान एवं विकास (R&D) वैश्विक प्रतिस्पर्धा को कमजोर करते हैं।



Pillars of Viksit Bharat



Sashakt Citizens • Strong Economy • Sustainable Future



PEOPLE

Empowered and inclusive citizens at the core of development



ECONOMY

Strong, resilient and globally competitive economy



INNOVATION

Innovation and technology driving growth and opportunities



INFRASTRUCTURE

World-class infrastructure connecting every aspiration



QUALITY OF LIFE

Good health, quality education and safe, fulfilling lives for all



SUSTAINABILITY

Environment conservation and sustainable development

राष्ट्रीय सुरक्षा और कानूनी आधार

- ❖ आधुनिक रक्षा प्रणाली पारंपरिक और गैर-पारंपरिक खतरों का मुकाबला करती है; कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ आतंकवाद, साइबर खतरों और संगठित अपराध से लड़ती हैं।
- ❖ साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण डिजिटल बुनियादी ढाँचे और संवेदनशील डेटा की रक्षा करती है, जबकि मजबूत डेटा कानून डिजिटल लचीलापन बढ़ाते हैं।
- ❖ संसाधन सुरक्षा ऊर्जा, खनिज और जल की रक्षा करती है; आपदा-रोधी क्षमता समुदायों, बुनियादी ढाँचे और आर्थिक स्थिरता की रक्षा करती है।
- ❖ कानून का शासन समय पर न्याय सुनिश्चित करता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और सामाजिक सद्भाव और अंतराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करता है।
- ❖ अनुबंध प्रवर्तन और भ्रष्टाचार रोधी तंत्र व्यावसायिक दक्षता, निवेशक विश्वास, नैतिक शासन, जवाबदेही और सार्वजनिक विश्वास में सुधार करते हैं।

वैश्विक साझेदारी और रणनीतिक प्रभाव

- ❖ अंतराष्ट्रीय बाजार और विदेशी निवेश व्यापार प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं, जिससे वैश्विक साझेदारियों के माध्यम से आर्थिक विकास को समर्थन मिलता है।
- ❖ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अनुसंधान एवं विकास सहयोग से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष और नवीकरणीय ऊर्जा में नवाचार को बढ़ावा मिलता है।
- ❖ संयुक्त अभ्यासों, खुफिया जानकारी साझा करने और रणनीतिक

गठबंधनों के माध्यम से सुरक्षा सहयोग रक्षा क्षमताओं, वैश्विक प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय हितों को मजबूत करता है।

- ❖ संयुक्त राष्ट्र, G 20 और ब्रिक्स सहित वैश्विक मंच भू-राजनीतिक प्रभाव, जलवायु परिवर्तन के शमन और सतत् विकास को बढ़ावा देते हैं।

निष्कर्ष

एकीकृत घरेलू क्षमताओं और वैश्विक सहभागिता के माध्यम से 2047 तक एक समृद्ध, सुरक्षित, न्यायसंगत और प्रभावशाली भारत का निर्माण किया जा सकता है।

2. क्षमता निर्माण के माध्यम से अवसरों का सृजन

परिचय

स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर विकसित भारत@2047 के लिए स्वस्थ नागरिक, भविष्य के लिए तैयार युवा, आपस में जुड़े हुए बसावट, उद्यमशीलता और पर्यावरण के अनुकूल विकास की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य के लिए तैयार कौशल

- ❖ मानव पूंजी प्राथमिक और निवारक देखभाल, पोषण, स्वच्छता, सुरक्षित पानी, मातृ-शिशु स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण पर निर्भर करती है।
- ❖ अगस्त 2026 तक 1.86 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों ने आयुष्मान भारत की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पहुँच को मजबूत किया।
- ❖ 20 जुलाई, 2026 तक, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने 94.87 करोड़ आभा आईडी बनाई, जिससे कनेक्टेड हेल्थकेयर तक पहुँच में सुधार हुआ।

- ❖ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 लचीले शैक्षणिक मार्गों के माध्यम से अनुभवात्मक, आलोचनात्मक, रचनात्मक और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देती है।
- ❖ नीति आयोग की विकसित भारत@2047 के लिए कौशल विकास की पुनर्कल्पना परियोजना आजीवन शिक्षा को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन और हरित प्रौद्योगिकी से संबंधित रोजगार परिणामों से जोड़ती है।

रोजगार और उद्यमिता

- ❖ भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए विनिर्माण, सेवाओं, कृषि-उद्योग, पर्यटन, रसद, निर्माण और डिजिटल अर्थव्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में सम्मानजनक काम की आवश्यकता है।
- ❖ अगस्त 2025 में शुरू की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) पहली बार रोजगार और नियोजता के नेतृत्व वाली औपचारिकता को प्रोत्साहित करती है।
- ❖ PM-VBRY योजना के तहत 1 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 के दौरान ईपीएफओ से जुड़े प्रोत्साहनों का उपयोग करते हुए ₹99,446 करोड़ के निवेश से 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियाँ सृजित करने का लक्ष्य है।
- ❖ सरकार के अनुसार, 31 मार्च, 2026 तक 1.23 लाख मान्यता प्राप्त स्टार्टअप ने 23.36 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियाँ सृजित की।
- ❖ 1.07 लाख से अधिक स्टार्टअप में महिला निदेशक या भागीदार थी; डीपीआईआईटी ने मार्च 2026 तक 1.02 लाख स्टार्टअप की गणना की।
- ❖ ₹10,000-स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 के तहत करोड़ों डॉलर के स्टार्टअप को डीप-टेक्नोलॉजी में निवेश करने का समर्थन प्राप्त है; लगभग आधे स्टार्टअप टियर-II/III शहरों से आते हैं।

अवसंरचना, ग्रामीण परिवर्तन और हरित विकास

- ❖ नीति आयोग की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)@2047 परियोजना किसानों और शिक्षार्थियों को जोड़ती है, जिसमें कृषि तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्राथमिकता दी जाती है।
- ❖ सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, उपयोगिताएँ और रसद व्यवस्था प्रसंस्करण, पर्यटन, हस्तशिल्प और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण विविधीकरण का समर्थन करते हैं।
- ❖ वीबी-जी राम जी अधिनियम 125 रोजगार दिवसों की गारंटी देता है, जिससे पानी, आजीविका और मौसम के हिसाब से मजबूत ग्रामीण संपत्तियाँ बनाई जाती हैं।
- ❖ नवीकरणीय ऊर्जा, दक्षता, हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, भंडारण, जैव ऊर्जा और अपशिष्ट-से-संसाधन मॉडल उद्योग, कौशल और रोजगार सृजित करते हैं।

निष्कर्ष

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 इस बात पर जोर देता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, अवसंरचना, ग्रामीण विकास और हरित विकास को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। विकसित भारत केवल आर्थिक आकार पर निर्भर नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण अवसरों और व्यापक नागरिक भागीदारी पर निर्भर करता है।

3. स्वास्थ्य ही विकास का इंजन है

परिचय

भारत के विकसित भारत@2047 लक्ष्य के लिए स्वस्थ, उत्पादक और आर्थिक रूप से सुरक्षित रहने हेतु दीर्घायु होना आवश्यक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संकेतक बीमा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल क्षमता के विस्तार को दर्शाते हैं।

मानव पूंजी के रूप में स्वास्थ्य

- ❖ भारत में जीवन प्रत्याशा 1947 में लगभग 30 वर्ष से बढ़कर 70 वर्ष हो गई; लेकिन स्वास्थ्य अवधि अभी भी अपर्याप्त है।
- ❖ भारत में 35 वर्ष से कम आयु के कई नागरिकों के साथ, कार्यात्मक स्वास्थ्य ही यह निर्धारित करता है कि भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को उत्पादकता में परिवर्तित कर पाता है या नहीं।
- ❖ सार्वजनिक स्वास्थ्य में निवेश से कामकाजी जीवन बढ़ता है, आय और उत्पादकता में वृद्धि होती है, जबकि गरीबी और स्वास्थ्य देखभाल व्यय में कमी आती है।
- ❖ कमजोर स्वास्थ्य प्रणालियाँ महामारी की चपेट में आने की संभावना, आर्थिक कठिनाई और रोजगार हानि को बढ़ाती हैं; सामाजिक बहिष्कार चिकित्सा सुविधाओं तक पहुँच को सीमित करता है।
- ❖ कोविड-19 ने स्वास्थ्य व्यवस्था की कमजोरी को उजागर किया, जबकि जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य, आवास, उत्पादकता और राष्ट्रीय आर्थिक लचीलेपन के लिए खतरा पैदा करता है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य विस्तार, 2014-2026

- ❖ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) ₹5 लाख का कवर देती है; 45.5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए।
- ❖ पीएम-जेएवाई योजना में 55 करोड़ लाभार्थी और 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक शामिल हैं, जिसके तहत 12.69 करोड़ अस्पताल में भर्ती होने के लिए 1.92 लाख करोड़ रुपये का वित्तपोषण किया जाता है।
- ❖ 1.86 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर ग्रामीण, शहरी और आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं, जहाँ 540 करोड़ से अधिक लोगों ने दौरा किया है।
- ❖ 96.43 करोड़ से ज्यादा आभा आईडी और 110 करोड़ से अधिक लिंक किए गए रिकॉर्ड ने डिजिटल स्वास्थ्य को मजबूत किया; ई-संजीवनी ने 49 करोड़ से अधिक परामर्श प्रदान किए।

- ❖ 18,646 जन औषधि केंद्रों पर 50-80% की बचत वाली दवाएँ मिलती हैं; मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 के 387 से बढ़कर 818 हो गई है।
- ❖ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने मातृ स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करते हुए 7.91 करोड़ मुफ्त प्रसवपूर्व जाँचें पूरी कीं।

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय सुरक्षा

- ❖ 2017-18-2025 के दौरान सरकारी स्वास्थ्य बीमा कवरेज में वृद्धि हुई: ग्रामीण क्षेत्रों में 12.9% से 45.5% और शहरी क्षेत्रों में 8.9% से 31.8%, जिससे वित्तीय सुरक्षा मजबूत हुई।
- ❖ किरायायती ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा बचत की रक्षा करती है, काम के छोटे हुए दिनों को कम करती है और कृषि, औद्योगिक और औपचारिक अर्थव्यवस्था में भागीदारी को मजबूत करती है।
- ❖ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, निक्षय मित्र, आशा कार्यकर्ता और इंद्रधनुष मिशन के माध्यम से टीकाकरण, पोषण और घर-घर जाकर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
- ❖ निक्षय पोषण योजना तपेदिक रोगियों की सहायता करती है; एनीमिया मुक्त भारत जीवन के सभी चरणों में पूरक आहार और कृमिनाशक दवाएँ प्रदान करता है।

निष्कर्ष

विकसित भारत का अर्थ है दीर्घायु के साथ-साथ स्वास्थ्य, स्फूर्ति और उत्पादकता को बढ़ाना, सामूहिक कल्याण और राष्ट्रीय समृद्धि को मजबूत करना।

4. नवाचार से बदलता ग्रामीण भारत

परिचय

ग्रामीण नवाचार खाद्य प्रसंस्करण, कृषि प्रौद्योगिकी, हस्तशिल्प, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल सेवाओं का विस्तार करता है। राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन (NIF) और इसके इनक्यूबेशन कार्यक्रम जमीनी स्तर के विचारों को वित्त, प्रौद्योगिकी और बाजारों से जोड़ते हैं।

नवाचार और इनक्यूबेशन पारिस्थितिकी तंत्र

- ❖ 2025-26 के दौरान, निधि-प्रयास ने 46 केंद्रों का संचालन किया, जिसमें 2,408 नवप्रवर्तकों, 1,790 प्रोटोटाइपों, 900 से अधिक पेटेंटों, ₹975 करोड़ और 8,800 नौकरियों का समर्थन किया।
- ❖ 2024-25 के दौरान, सुनील ने 25 परियोजनाओं का समर्थन किया, जिनमें आठ नई परियोजनाएँ शामिल थीं; एसटीआई हब में 13 एससी और सात एसटी केंद्र शामिल थे।
- ❖ वर्ष 2000 से, एनआईएफ ने 730 जिलों से 3.75 लाख विचारों का दस्तावेजीकरण किया है, 1,145 नवप्रवर्तकों को मान्यता दी है, 1,478 पेटेंट दाखिल किए हैं और 120 लाइसेंस जारी करने में मदद की है।

- ❖ जून 2026 तक, स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ने 4.32 लाख उद्यमों को सहायता प्रदान की; इनमें से 86% उद्यमी वंचित समुदायों से थे।
- ❖ जून 2026 तक, 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फैले ASPIRE के 109 इनक्यूबेटरों ने 1.23 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया, जिससे 1,200 माइक्रो-एंटरप्राइज (छोटे उद्यम) शुरू करने में मदद मिली।
- ❖ अप्रैल 2022 से फरवरी 2026 के दौरान, ASPIRE ने 28,500 महिलाओं, 8,700 अनुसूचित जातियों, 9,600 अनुसूचित जनजातियों और 17,600 अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों तक अपनी पहुँच बनाई।

उद्यम विकास और बाजार समर्थन

- ❖ PMFME ने दिसंबर 2025 तक 59,202 इकाइयों को औपचारिक रूप दिया; जुलाई 2026: दो लाख ऋणों के माध्यम से ₹17,015.8 करोड़ जुटाए गए, जिनमें से लगभग 90% पहली पीढ़ी के थे और 44% महिलाएँ थीं।
- ❖ SVEP के मूल्यांकन में पाया गया कि इसके नमूने में 99% लाभप्रदता, 57% घरेलू आय योगदान, ₹39,000 मासिक राजस्व और 75% महिला स्वामित्व वाले उद्यम शामिल हैं।
- ❖ SVEP, एस्पायर, RSETIs और नाबार्ड वित्त, प्रशिक्षण व इनक्यूबेशन को एकीकृत करते हैं; डीएसटी-निधि, AIM और DBT-BIRAC प्रौद्योगिकी उद्यमों का समर्थन करते हैं।
- ❖ RKVY-RAFTAAR ने वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 1,943 कृषि स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान की; MANAGE-CIA ने 562 स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट किया और 1,100 इच्छुक उद्यमियों को मेंटरशिप प्रदान की।
- ❖ महाएग्री-एआई नीति 2025-29 के तहत तीन वर्षों में ₹500 करोड़ आवंटित किए गए हैं; केरल की केईआरए ने 150 स्टार्टअप के लिए इनक्यूबेशन सहायता का लक्ष्य रखा है।

सफल मॉडल और ग्रामीण परिवर्तन

- ❖ 2024-25 में, अमूल के सहकारी मॉडल ने 18,600 ग्राम समितियों और 3.64 मिलियन उत्पादकों के माध्यम से ₹65,911 करोड़ का टर्नओवर हासिल किया।
- ❖ भाग्यश्री लॉन्गे के ₹45,000 के एसवीईपी ऋण से दस दिनों में ₹5 लाख प्राप्त हुए; पूनम ने लगभग 40 उद्यमों को मार्गदर्शन दिया।
- ❖ अप्रैल 2026 तक, 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 50 से अधिक बायोटेक-किसान केंद्रों ने एक लाख किसानों तक पहुँच बनाई, जिससे उपज में 15-37% की वृद्धि हुई।
- ❖ ओडिशा, असम और आंध्र प्रदेश ने उर्वरक का उपयोग 25-30% तक कम किया; राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने दलहन और मूंगफली की पैदावार 20-35% तक बढ़ाई।

- ❖ बायोटेक-किसान ने 5,000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया और 1,200 से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए; महिला बायोटेक फेलोशिप और मशरूम मेंटर ने नवाचार को बढ़ावा दिया।
- ❖ 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी, वीबी-जी राम जी अधिनियम 2025 ने गारंटीकृत रोजगार को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में उत्पादक संपत्तियाँ बनाने में मदद मिलेंगी।

निष्कर्ष

ग्रामीण उद्यम को बढ़ावा देने के लिए औपचारिक ऋण, भंडारण, कोल्ड चेन, विश्वसनीय बिजली, डिजिटल कनेक्टिविटी, उन्नत कौशल, मार्गदर्शन और बाजार तक पहुँच आवश्यक है। सरकार, अनुसंधान संस्थानों, उद्योग, स्टार्टअप, किसानों और सामुदायिक संस्थानों के बीच सहयोग से विकसित भारत@2047 को आगे बढ़ाया जा सकता है।

5. आत्मनिर्भर भारत के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त बनाना

परिचय

विकसित भारत@2047 के लिए जरूरी है कि गाँव स्थानीय संसाधनों, मूल्यवर्धन, उद्यमिता और बाजारों को जोड़कर विकास के इंजन बनें।

स्थानीय उद्यमों का निर्माण

- ❖ खेती, पशुपालन, मछली पालन, बागवानी, हस्तशिल्प और वन उत्पादों जैसे ग्रामीण स्थानीय संसाधनों से कई तरह के उद्यम शुरू किए जा सकते हैं।
- ❖ यह मार्ग संसाधन पहचान, सामूहिक संगठन, मूल्यवर्धन और उद्यम निर्माण को बाजार पहुँच और सतत् विकास से जोड़ता है।
- ❖ अनाज, दालें, तिलहन, फल, सब्जियाँ, मसाले और दूध के प्रसंस्करण से स्थानीय मूल्य और सेवा क्षेत्र में रोजगार का सृजन होता है।
- ❖ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट फ्रेमवर्क, विशिष्ट जिलों की खूबियों को प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और बाजार विकास के साथ जोड़ता है।
- ❖ महिला समूह, उत्पादक संगठन, सहकारी समितियाँ और समूह साझा बुनियादी ढाँचे, सौदेबाजी क्षमता और उद्यम की व्यवहार्यता में सुधार करते हैं।

सरकारी सहायता और संस्थागत ढाँचा

- ❖ दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने 12 अगस्त, 2026 तक 10.19 करोड़ परिवारों को 94.46 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया।
- ❖ DAY-NRLM के तहत, स्टार्ट-अप विलेज इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ने वित्त और मार्गदर्शन के माध्यम से 2026 तक 4.32 लाख से अधिक ग्रामीण उद्यमों को सहायता प्रदान की।
- ❖ सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकरण के लिए प्रधानमंत्री की पहल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दृष्टिकोण के माध्यम से उन्नयन, बुनियादी ढाँचे और ब्रांडिंग में सहयोग प्रदान करती है।

- ❖ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ने अपनी स्थापना के बाद से 30 लाख ग्रामीण उद्यमों सहित 41 लाख से अधिक इकाइयों को सहायता प्रदान की है।
- ❖ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना प्रशिक्षण, उपकरण किट, ऋण और बाजार सहायता के माध्यम से कारीगरों को सशक्त बनाती है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले कौशल का संरक्षण होता है।
- ❖ पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के लिए कोष की योजना (स्फूर्ति) की रिपोर्ट के अनुसार, 513 अनुमोदित क्लस्टर हैं, जिनमें 376 कार्यात्मक क्लस्टर शामिल हैं।

बाजार, स्थिरता और अभिसरण

- ❖ डिजिटल भुगतान, कैटलॉग, ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया से ग्राहकों की संख्या बढ़ती है, लेकिन गुणवत्ता, मूल्य निर्धारण और उपभोक्ता प्रतिक्रिया ही प्रतिस्पर्धात्मकता निर्धारित करते हैं।
- ❖ हरित उद्यम कृषि अवशेषों, बाँस और प्राकृतिक रेशों को उत्पादों में परिवर्तित करते हैं, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन लागत को कम करती है।
- ❖ पंचायतें और स्थानीय संस्थाएँ उत्पादकों की क्षमताओं की पहचान करती हैं, कार्यक्रमों का समन्वय करती हैं और उत्पादकों को वित्त, कौशल और बाजारों से जोड़ती हैं।
- ❖ जिला और ब्लॉक स्तरों पर समन्वित समर्थन से मार्गदर्शन, वित्त, उत्पादन, गुणवत्ता और बाजारों को जिम्मेदार विकास के लिए आपस में जोड़ा जाना चाहिए।

निष्कर्ष

व्यापक बाजारों से जुड़े आत्मनिर्भर गाँव स्थानीय मूल्य, उद्यम, रोजगार और समृद्धि का सृजन कर सकते हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगी।

6. साझा समृद्धि के लिए सहकारी समितियाँ

परिचय

विकसित भारत@2047 के लिए ऐसे सामुदायिक संस्थानों की आवश्यकता है जो मृदा स्वास्थ्य, सामूहिक कार्रवाई और मूल्य सृजन को किसानों की मजबूत आजीविका से जोड़ें।

सामूहिक खेती और मूल्य सृजन

- ❖ छोटे और सीमांत किसानों को महँगी लागत, खंडित जोत, सीमित भंडारण, वित्त और लाभकारी बाजार पहुँच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- ❖ सहकारी समितियाँ और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) इनपुट की मांग, मशीनरी और योजना को एक साथ लाते हैं, जिससे खेती की लागत कम हो जाती है।
- ❖ सामूहिक विपणन से बिचौलियों पर निर्भरता कम होती है, मोल-भाव करने की क्षमता मजबूत होती है और उपज को एक साथ बेचने से बेहतर कीमत मिलती है।

- ❖ ग्राम संस्थाएँ वर्गीकरण, भंडारण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग को सक्षम बनाती हैं, जिससे स्थानीय रोजगार और कृषि से होने वाली आय में वृद्धि होती है।
- ❖ साझा संसाधन प्रबंधन मिट्टी, जल, प्रौद्योगिकी, उत्पादन और बाजारों को आपस में जोड़ता है, जिससे आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण होता है।

मृदा स्वास्थ्य और कृषि समृद्धि

- ❖ मृदा स्वास्थ्य, भले ही व्यक्तिगत स्वामित्व में हो, एक सामुदायिक संपत्ति के तौर पर काम करती है जो उत्पादकता और ग्रामीण इलाकों की दीर्घकालिक समृद्धि पर असर डालती है।
- ❖ लगभग 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोषक तत्वों पर आधारित, फसल-विशिष्ट सिफारिशें प्रदान करते हैं, जिससे संतुलित उर्वरक उपयोग संभव हो पाता है।
- ❖ कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से 7.2 लाख प्रदर्शनों ने संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा दिया।
- ❖ 70,002 कृषि सखियों को अंतिम छोर के सलाहकार के रूप में प्रशिक्षित किया गया, जिससे मृदा स्वास्थ्य सेवाओं के ग्राम स्तर पर वितरण को मजबूत किया जा सके।
- ❖ मृदा परीक्षण और मानचित्रण जैविक पदार्थ की बहाली, जैव उर्वरकों, अवशेषों के पुनर्चक्रण और उपयुक्त फसल चक्रों में मार्गदर्शन करते हैं।
- ❖ सोयाबीन, दालों, गेहूँ और मोटे अनाजों की सामूहिक प्रसंस्करण से बाजार तक पहुँच, खेती से होने वाली कमाई और स्थानीय स्तर पर मूल्यवर्धन में सुधार होता है।

समावेशी और चक्रीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था

- ❖ स्वयं सहायता समूह महिलाओं को बीज, खाद, जैविक इनपुट, खाद्य प्रसंस्करण और विपणन में शामिल करते हैं, जिससे आर्थिक भागीदारी मजबूत होती है।
- ❖ ग्रामीण युवा मृदा परीक्षण, मशीनरी, डिजिटल कृषि, मौसम और बाजार सेवाएँ प्रदान करते हैं, जिससे स्थानीय नवाचार और रोजगार को बढ़ावा मिलता है।
- ❖ डिजिटल प्लेटफॉर्म मौसम, मिट्टी, कीट, योजना और मूल्य संबंधी जानकारी प्रदान करते हैं, साथ ही एकत्रीकरण और प्रत्यक्ष विपणन को सक्षम बनाते हैं।
- ❖ चक्रीय ग्रामीण उद्यम बायोमास, फसल अवशेषों और पशु अपशिष्ट को खाद, वर्मीकंपोस्ट और विपणन योग्य जैविक इनपुट में परिवर्तित करते हैं।

निष्कर्ष

संगठित सामुदायिक कार्रवाई लागत को कम कर सकती है, मूल्य बढ़ा सकती है, रोजगार सृजित कर सकती है, प्रवासन को सीमित कर सकती है और जलवायु-अनुकूल ग्रामीण समृद्धि का निर्माण कर सकती है।

7. जलवायु-अनुकूल ग्रामीण अवसंरचना

परिचय

जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बुनियादी ढाँचे को बाढ़, सूखे और भीषण गर्मी से ग्रामीण आजीविका की रक्षा करनी चाहिए, साथ ही यह किफायती और टिकाऊ भी होना चाहिए। मिशन मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियों के माध्यम से कृषि, मत्स्य पालन, विमानन और आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाता है।

जलवायु जोखिम और ग्रामीण भेद्यता, 1995-2024

- ❖ जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में 9,700 ऐसी घटनाओं का उल्लेख है जो 5.6 अरब लोग प्रभावित हुए, 832,000 मौतें हुईं और 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ।
- ❖ भारत नौवें स्थान पर रहा, जहाँ लगभग 430 घटनाएँ हुईं, 170 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ, एक अरब लोग प्रभावित हुए और 80,000 से अधिक मौतें हुईं।
- ❖ CEEW ने 638 मिलियन लोगों की आबादी वाले भारत के 75% से अधिक जिलों को चरम जलवायु हॉटस्पॉट के रूप में पहचान किया है।
- ❖ 2005 के बाद, 15 वर्षों में 310 घटनाएँ हुईं, जबकि 1970-2005 के दौरान 250 घटनाएँ हुई थीं; बाढ़ की घटनाएँ आठ गुना बढ़ गईं, जिससे सालाना 97 मिलियन लोग प्रभावित हुए।

नवीकरणीय ऊर्जा और लचीली अवसंरचना

- ❖ राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का अनुमान है कि भारत की बंजर भूमि के केवल 3% हिस्से का उपयोग करके 748 गीगावाट सौर ऊर्जा की क्षमता प्राप्त की जा सकती है।
- ❖ भारत में 164.59 गीगावाट सौर ऊर्जा, 58.14 गीगावाट पवन ऊर्जा, 57.24 गीगावाट जलविद्युत, 11.75 गीगावाट जैव-विद्युत और 8.78 गीगावाट परमाणु ऊर्जा की क्षमता है।
- ❖ 2025-26 के दौरान, भारत ने रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जिसमें 44.6 गीगावाट सौर ऊर्जा और 6 गीगावाट पवन ऊर्जा शामिल है।
- ❖ मोदेरा में लगाए गए 1,300 रूफटॉप पैनलों से बिजली के बिल खत्म हो गए; हिमाचल प्रदेश में 728.4 मेगावाट की सौर परियोजनाओं में प्रगति हुई।
- ❖ 23,731 करोड़ रुपये के बजट के साथ 2026-27 के लिए शुरू की गई गोबरधन योजना जैविक कचरे को स्वच्छ ईंधन, खाद और ग्रामीण आय में परिवर्तित करती है।
- ❖ जुलाई 2025 तक PMGSY ने अपशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग करके 43,700 किमी सड़क का निर्माण किया गया; पात्र कार्यों में से 70% में इसका उपयोग अनिवार्य हो गया।

हरित भवनों, सड़कों और जल सुरक्षा

- ❖ भारत में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का एक तिहाई हिस्सा इमारतों

से उत्पन्न होता है; अंतर्निहित कार्बन इस क्षेत्र के कुल उत्सर्जन का लगभग आधा हिस्सा है।

- ❖ तमिलनाडु के जलवायु-अनुकूल गाँव 11 जिलों में 27 लाख तक पहुँच गए हैं; गुजरात ने 271 किलोमीटर लंबी 20 जलवायु-अनुकूल सड़कों के लिए ₹1,147 करोड़ आवंटित किए हैं।
- ❖ दस में से नौ प्राकृतिक आपदाएँ जल से संबंधित थीं; दस वर्षों में मौतों की संख्या दोगुनी हो गई, जिसके कारण 2010-19 के दौरान 95% बुनियादी ढाँचे का नुकसान हुआ।
- ❖ 2000-19 के दौरान, सूखे से 1.4 अरब लोग और बाढ़ से 1.6 अरब लोग प्रभावित हुए, जिसके लिए प्रकृति-आधारित अनुकूलन की आवश्यकता पड़ी।
- ❖ जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए), जिसे 2011 में शुरू किया गया था, ने 151 संवेदनशील जिलों में 448 गाँवों की स्थापना की।
- ❖ राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (NMSA) के तहत 2014-15 में शुरू किया गया यह मिशन वर्षा आधारित विकास, मृदा स्वास्थ्य और जल दक्षता को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष

जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन को स्वच्छ ऊर्जा, जल संरक्षण, स्थानीय सामग्रियों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से योजना, निर्माण, रखरखाव और नवीनीकरण का मार्गदर्शन करना चाहिए।

8. पंचायत, स्वयं सहायता समूह एवं युवाओं को सशक्त बनाना

परिचय

जमीनी स्तर पर परिवर्तन के लिए पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और युवाओं के बीच समन्वय आवश्यक है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की 2024 की समीक्षा में अनुच्छेद 243G के अंतर्गत ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों में राज्यों के बीच व्यापक भिन्नता पाई गई।

हस्तांतरण और डिजिटल शासन

- ❖ 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992, जो 1993 से प्रभावी हुआ, ने 24.04 लाख प्रतिनिधियों सहित 2.5 लाख पंचायतों का गठन किया, जिनमें 49.75% महिलाएँ शामिल थीं।
- ❖ दीनदयाल अंत्योदय योजना— राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने 10.05 करोड़ परिवारों को 92 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया, जिससे आजीविका और सामाजिक पूंजी को मजबूती मिली।
- ❖ पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2021-26 के लिए ₹2.368 लाख करोड़ की सिफारिश की थी; सोलहवें आयोग ने 2026-31 के लिए ₹4.35 लाख करोड़ का प्रस्ताव रखा था।
- ❖ 2025-26 के दौरान, ई-ग्रामस्वराज-PFMS ने ₹53,342 करोड़

हस्तांतरित किए; 2.55 लाख ग्राम पंचायतों ने विकास योजनाएँ अपलोड कीं।

- ❖ ई-ग्रामस्वराज ने 2,59,798 पंचायती राज संस्थाओं को अपने साथ जोड़ा, 2,50,807 ऑनलाइन भुगतान संस्थानों को सक्षम बनाया और 1,60,79,737 विक्रेताओं को पंजीकृत किया।
- ❖ सभासार ने 1.36 लाख पंचायतों, 23 भाषाओं और 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 3.6 लाख बैठक मिनट तैयार किए।



अभिसरण और जमीनी स्तर की भागीदारी

- ❖ ग्राम पंचायतें जन-योजना अभियान के तहत GDPDs तैयार करती हैं, जबकि स्वयं सहायता समूह संघ मिलकर ग्राम समृद्धि और लचीलापन योजनाएँ तैयार करने में सहयोग करते हैं।
- ❖ जुलाई 2026 तक, एसएचजी बैंक लिंकेज पोर्टल ने ₹13,41,852.66 करोड़ के ऋण वितरण को दर्ज किया, जिससे उद्यम और आजीविका विस्तार को समर्थन मिला।
- ❖ अक्टूबर 2025 में शुरू की गई मॉडल यूथ ग्राम सभा, त्रिस्तरीय शासन, सहभागिता और युवा नेतृत्व की समझ विकसित करती है।
- ❖ चेम्बिलोड ग्राम पंचायत ने सूचनाएँ जारी करने के लिए कुडुम्बश्री नेटवर्क का उपयोग किया; बोकरो और धनबाद ने पंचायती राज दिवस को लोकतंत्र के उत्सव के रूप में मनाया।
- ❖ गांधार ग्राम पंचायत ने 'पहले नाली, बाद में सड़क' की नीति अपनाई; मेराल ईस्ट ने व्हाट्सएप, फेसबुक और पंचायत ऐप के माध्यम से जनसंपर्क का संयोजन किया।

चुनौतियाँ और सुधार प्राथमिकताएँ

- ❖ ग्राम सभा में भागीदारी आजीविका संबंधी कार्यक्रमों, खराब संचार व्यवस्था, लैंगिक बाधाओं, अधिकारियों की अनुपस्थिति और शिकायतों के प्रति कमजोर प्रतिक्रिया के कारण बाधित रहती है।
- ❖ सीमित स्व-स्रोत राजस्व, संस्थागत अलगाव, डिजिटल अंतराल और कमजोर बाजार संबंध उत्तरदायी स्थानीय विकास को बाधित करते हैं।
- ❖ सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान, महिला-अनुकूल पंचायतों और मॉडल युवा ग्राम सभाओं का विस्तार किया जाए, साथ ही स्थानीय भाषा में प्रशिक्षण और सहकर्मि मार्गदर्शन को बढ़ावा दिया जाए।
- ❖ राजकोषीय विकेंद्रीकरण, समर्थ-आधारित राजस्व, समावेशी ग्राम सभाएँ और सभासार-सक्षम जवाबदेही से पंचायत उन्नति सूचकांक के परिणामों को मजबूती मिलनी चाहिए।

निष्कर्ष

गहन सत्ता एवं अधिकारों का विकेंद्रीकरण, निरंतर क्षमता निर्माण तथा तकनीक-सक्षम समन्वय के माध्यम से पंचायतें, स्वयं सहायता समूह और युवा मिलकर समावेशी विकसित भारत@2047 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

9. पंच प्रणाली : सक्रिय अधिगम के लिए एक नया दृष्टिकोण

परिचय

पंच प्रणाली श्रवण, स्मरण, तैयारी, प्रस्तुति और सुदृढ़ीकरण को एकीकृत करती है ताकि अधिगम सक्रिय, सहभागी और स्थायी बन सके।

रूपरेखा एवं अधिगम परिणाम

- ❖ इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरीएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट (आईएसटीएम) ने निष्क्रिय प्रशिक्षण को शिक्षार्थी-संचालित सुदृढ़ीकरण में बदलने के लिए पंच प्रणाली विकसित की।
- ❖ 5×5×5 का ढाँचा पाँच दैनिक सत्रों, पाँच यादृच्छिक रूप से चयनित प्रतिभागियों और अगली सुबह होने वाली पाँच प्रस्तुतियों को आपस में जोड़ता है।
- ❖ इसका अधिगम चक्र सुनने, याद करने, तैयारी करने, प्रस्तुत करने और सुदृढ़ करने के चरणों से गुजरता है, जिससे एक बार का निर्देश निरंतर सहभागिता में परिवर्तित हो जाता है।
- ❖ यादृच्छिक चयन से उत्सुकता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है, जबकि प्रस्तुतियाँ समझ, संचार, आत्मविश्वास और शिक्षार्थी की जवाबदेही को गहरा करती हैं।
- ❖ स्पष्टीकरण तैयार करने के लिए आवश्यक तत्वों को अलग करना, जानकारी को व्यवस्थित करना और कमियों की पहचान करना, ज्ञान को व्यावहारिक दक्षता में बदलना आवश्यक है।
- ❖ पंच प्रणाली के लिए बहुत कम अतिरिक्त बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता होती है, यह सक्रिय भागीदारी और सुदृढ़ीकरण को बनाए रखते हुए सत्रों और प्रतिभागियों को अनुकूलित करती है।

शैक्षिक आधार और व्यापक अनुप्रयोग

- ❖ श्रवण, मनन, निदिध्यासन और अभ्यास भारत की शिक्षण परंपराओं में सुनने, चिंतन करने, आत्मसात करने और अभ्यास करने की प्रक्रिया को आपस में जोड़ते हैं।
- ❖ आधुनिक पुनर्प्राप्ति अभ्यास, चिंतन और सहकर्मि स्पष्टीकरण रिचर्ड फेनमैन के शिक्षण-द्वारा-सीखने के सिद्धांत के समानांतर हैं, जो वैचारिक निपुणता को मजबूत करते हैं।
- ❖ फ्लिपड क्लासरूम और सहकर्मि निर्देश पंच प्रणाली की तैयारी, व्याख्या और भागीदारी के समानांतर चलते हैं, जिससे सक्रिय अधिगम को मजबूती मिलती है।
- ❖ राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति 2012 ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को एकीकृत करती है; मिशन कर्मयोगी योग्यता-आधारित और नागरिक-केंद्रित लोक सेवा को बढ़ावा देता है।
- ❖ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप, यह मॉडल प्रशिक्षकों, सिविल सेवाओं, स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों तक फैला हुआ है।

निष्कर्ष

पंच प्रणाली एक कम लागत वाली सीख को मजबूत करने की व्यवस्था है, जो सीखने की प्रक्रिया को केवल याद करने से आगे बढ़ाकर आत्मसात करने, अपने शब्दों में व्यक्त करने और व्यवहार में लागू करने की ओर ले जाती है।

10. सतत विकास के लिए नवीकरणीय ऊर्जा

परिचय

नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा, ग्रामीण आजीविका, रोजगार और तकनीकी नवाचार को मजबूत करती है, साथ ही भारत के सतत विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में मदद करती है।

नवीकरणीय ऊर्जा की प्रगति और प्रमुख योजनाएँ

- ❖ 30 जून, 2026 तक, नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता 288.59 गीगावाट तक पहुँच गई, जिसमें 162.15 गीगावाट सौर ऊर्जा और 57.44 गीगावाट पवन ऊर्जा शामिल है।
- ❖ भारत ने जून 2025 में जीवाश्म ईंधन के बिना स्थापित क्षमता का 50% लक्ष्य हासिल कर लिया, जो कि पाँच साल पहले है; वर्ष 2030 तक 500 GW का लक्ष्य रखा गया है।
- ❖ राष्ट्रीय सौर मिशन 2010 के बाद, क्षमता 2014 में 3 गीगावाट से बढ़कर 2026 तक 162 गीगावाट हो गई।
- ❖ प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना, फरवरी 2024 में शुरू की गई, जिसका 2026-27 तक एक करोड़ घरों तक पहुँच का लक्ष्य है।
- ❖ वर्ष 2025-26 के दौरान, 18.71 लाख रूफटॉप सिस्टम ने 6.7 गीगावाट बिजली जोड़ी; 48 लाख परिवारों को लाभ हुआ, जिससे अनुमानित 17 लाख नौकरियों का समर्थन मिला।

- ❖ प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) ने ₹34,422 करोड़ के समर्थन के साथ मार्च 2026 तक 34,800 मेगावाट का लक्ष्य रखा था।



स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करना

- ❖ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन उत्पादन, उपयोग और निर्यात का समर्थन करता है और इस्पात, रसायन, उर्वरक, परिवहन एवं जहाजरानी को कार्बन मुक्त करने में मदद करता है।
- ❖ राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम कृषि, औद्योगिक और शहरी कचरे को बायोगैस, बिजली और बायोसीएनजी में परिवर्तित करता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में चक्रीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलता है।
- ❖ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइनों और सबस्टेशनों का विकास करता है, जिससे दूरस्थ नवीकरणीय ऊर्जा से समृद्ध क्षेत्रों को राष्ट्रीय ग्रिड में एकीकृत किया जा सके।
- ❖ सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट सामान्य बुनियादी ढाँचा, पारेषण और सहायक सुविधाएँ प्रदान करते हैं, जिससे बड़े प्रोजेक्टों की बाधाएँ कम हो जाती हैं।
- ❖ भंडारण, पूर्वानुमान और लचीले ग्रिड विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं, जबकि भूमि दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण पर्यावरणीय स्थिरता की रक्षा करते हैं।

ग्रामीण परिवर्तन और हरित रोजगार

- ❖ सौर सिंचाई, छत पर लगे सौर ऊर्जा तंत्र, स्ट्रीट लाइटिंग और बायोगैस से गाँवों की ऊर्जा लागत कम होती है और सामुदायिक उद्यमों को बढ़ावा मिलता है।
- ❖ पीएम-कुसुम और पीएम सूर्य घर योजनाओं को ग्रामीण कार्यक्रमों

से जोड़ना स्वच्छ ऊर्जा, पंचायतों और सामुदायिक भागीदारी को आपस में जोड़ता है।

- ❖ सौर ऊर्जा उत्पादन, बैटरी भंडारण, हरित हाइड्रोजन, विद्युत गतिशीलता और स्मार्ट ग्रिड स्वच्छ ऊर्जा मूल्य शृंखला में रोजगार सृजित करते हैं।
- ❖ भविष्य की प्राथमिकताओं में क्षमता वृद्धि, घरेलू विनिर्माण और संचरण, विकेंद्रीकरण, कुशल श्रमिक, नवोन्मेषी वित्त और केंद्र-राज्य सहयोग शामिल हैं।

निष्कर्ष

नवीकरणीय ऊर्जा को केवल बिजली उत्पादन तक सीमित न रहकर रोजगार, ग्रामीण आजीविका, घरेलू विनिर्माण, आयात पर निर्भरता कम करने और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

11. विकसित भारत के लिए ग्रामीण रोजगार की पुनर्कल्पना

परिचय

विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025, मनरेगा को रोजगार, बुनियादी ढाँचे और संपत्ति सृजन के ढाँचे से प्रतिस्थापित करता है।

ग्रामीण रोजगार का संरचनात्मक परिवर्तन

- ❖ भारत की लगभग 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जिससे रोजगार योजनाएँ आय सुरक्षा और समावेशी विकास की आधारशिला बन जाती हैं।
- ❖ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 ने देशव्यापी स्तर पर 100 दिनों का मांग आधारित रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की।
- ❖ 1 जुलाई 2026 से प्रभावी, जी-आरएएम-जी अधिनियम 2025, 125 दिनों के काम की गारंटी देता है, लेकिन केवल केंद्र द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में ही।
- ❖ यह अधिनियम मांग-आधारित सार्वभौमिक पहुँच को मानदंड-आधारित, बजट-सीमित आवंटन से प्रतिस्थापित करता है, जिससे लागत पूर्व-निर्धारित हो जाती है लेकिन सार्वभौमिक पात्रता कमजोर हो जाती है।
- ❖ विकसित ग्राम पंचायत योजनाएँ भू-स्थानिक नियोजन का उपयोग करती हैं, उन्हें ऊपर की ओर समेकित करती हैं और पीएम गति शक्ति अवसंरचना कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करती हैं।
- ❖ निगरानी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जियोटैगिंग और प्रबंधन सूचना प्रणालियों का उपयोग किया जाता है, जबकि ग्राम पंचायत कार्यान्वयन वास्तविक समय की जवाबदेही को मजबूत करता है।

मुख्य विशेषताएँ और विकासात्मक फोकस

- ❖ साप्ताहिक वेतन भुगतान, जो 15 दिनों तक सीमित है, बैंक या डाक खातों के माध्यम से किया जाता है, जिससे पारदर्शिता और वित्तीय जवाबदेही में सुधार होता है।

- ❖ कृषि क्षेत्र में श्रम की उपलब्धता बनाए रखने के लिए, बुवाई और कटाई के दौरान सार्वजनिक निर्माण कार्य 60 दिनों के लिए स्थगित किया जा सकता है।
- ❖ महिलाओं की कम से कम एक-तिहाई भागीदारी अनिवार्य है जिसमें कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है और कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाता है।
- ❖ रोजगार से टिकाऊ ग्रामीण संपत्तियों का निर्माण होता है जो जल सुरक्षा, बुनियादी ढाँचे, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, आजीविका और जलवायु अनुकूलन का समर्थन करती हैं।
- ❖ ग्राम सभाएँ और पंचायतें कार्यों का चयन करती हैं, योजनाओं का समन्वय करती हैं और सामुदायिक सामाजिक लेखापरीक्षाएँ संचालित करती हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर स्वामित्व की भावना मजबूत होती है।

अपेक्षित लाभ और चिंताएँ

- ❖ आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, 45% ग्रामीण

श्रमिक कम उत्पादकता वाली कृषि में कार्यरत हैं, जिसके लिए गैर-कृषि विविधीकरण की आवश्यकता है।

- ❖ योजनाबद्ध परिसंपत्ति निर्माण से जल, बाजार तक पहुँच, घरेलू आय और स्थानीय उपभोग में सुधार होता है, जबकि संकटग्रस्त प्रवासन में कमी आती है।
- ❖ बजट की पूर्वानुमानशीलता से दक्षता में सुधार हो सकता है, लेकिन आपूर्ति-आधारित आवंटन से अधिकार-आधारित रोजगार सुरक्षा और आय स्थिरता के कमजोर होने का जोखिम है।
- ❖ अधिकार-आधारित सुरक्षा उपाय और उत्पादकता समर्थन, गरीबी पर सतत् विकास लक्ष्य 1 और सभ्य कार्य पर लक्ष्य 8 का समर्थन करते हैं।

निष्कर्ष

उत्पादक परिसंपत्तियाँ और डिजिटल शासन ग्रामीण समृद्धि को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन सुधारों में सामाजिक सुरक्षा, समय पर मजदूरी और आय स्थिरता को बनाए रखना आवश्यक है।

